



## भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी: यूरोपीय संघ के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी

24 जनवरी 2026

### मुख्य बातें

- ईयू के साथ भारत की भागीदारी यूरोप पर उसके रणनीतिक फोकस को दिखाती है, जो आने वाले भारत-EU शिखर सम्मेलन और चल रहे मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप है।
- 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार का वॉल्यूम लगभग \$136 बिलियन तक पहुंच गया, जिससे EU भारत का सबसे बड़ा सामान व्यापार भागीदार बन गया।
- 2019 और 2024 के बीच, भारत-EU सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हुई, जिसमें भारतीय निर्यात €19 बिलियन से बढ़कर €37 बिलियन हो गया और भारत को EU का निर्यात बढ़कर €29 बिलियन हो गया।
- 2024 तक, 931,607 से ज्यादा भारतीय EU में रहते थे, जिनमें 16,268 ब्लू कार्ड धारक शामिल थे, और पिछले 20 सालों में, 6,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति मिली, जो भारत-EU गतिशीलता और शैक्षिक संबंधों को उजागर करता है।

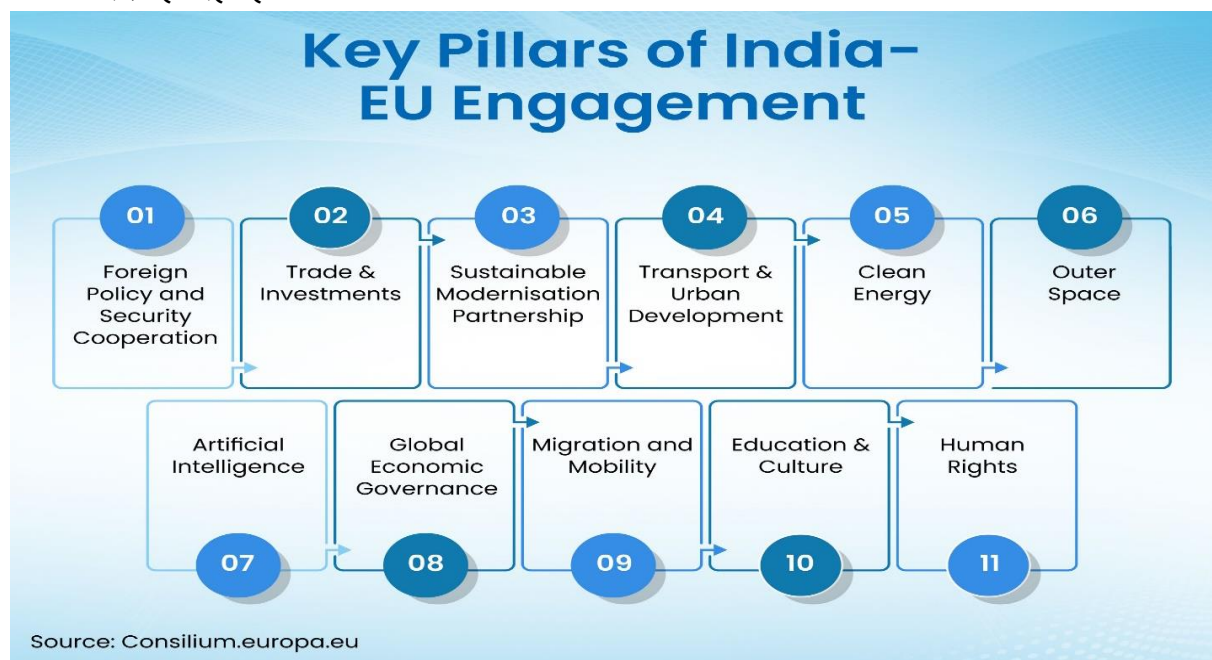
### परिचय

भारत-यूरोपीय संघ के रिश्ते एक नए रणनीतिक दौर में प्रवेश कर गए हैं, जिसमें दोनों पक्ष नई दिल्ली में होने वाले आगामी भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले बातचीत तेज़ कर रहे हैं। भारत और यूरोपीय संघ लंबे समय से अटके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मौजूदा रोडमैप से आगे साझेदारी को ले जाने के लिए एक नया संयुक्त रणनीतिक एजेंडा अपनाना चाहते हैं। यह चल रही बातचीत व्यापार, निवेश, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और रक्षा, डिजिटल पहलों, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और कृषि के क्षेत्रों में आपसी प्रतिबद्धता को दिखाती है। हाल के वर्षों में भारत-यूरोपीय संघ के उच्च-स्तरीय संबंध मज़बूत हुए हैं, जिसमें राष्ट्रपति उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व में यूरोपीय संघ कॉलेज ऑफ़ कमिशनर्स ने फरवरी 2025 में नई दिल्ली का दौरा किया - यह यूरोप के बाहर किसी द्विपक्षीय साझेदार का पहला ऐसा दौरा था। नेताओं ने G7 और G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों के मौके पर भी मुलाकात की, सबसे हाल ही में जून 2025 में कनाडा में,

और टेलीफोन पर बातचीत के ज़रिए नियमित संपर्क बनाए रखा, जिसमें सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वॉन डेर लेयेन और राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा के बीच कॉल शामिल हैं।

## भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का अवलोकन

भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध साझा मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिसमें लोकतंत्र, कानून का शासन, नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और प्रभावी बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। ये संबंध व्यापार और निवेश, सुरक्षा और रक्षा, जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, कनेक्टिविटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित एक व्यापक दायरे को कवर करते हैं। यूरोपीय संघ वस्तुओं के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में लगभग \$136 बिलियन तक पहुँच गया है। यूरोपीय संघ वस्तुओं और सेवाओं दोनों में भारत के शीर्ष समग्र व्यापारिक भागीदारों में से भी एक है। 'भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी: 2025 के लिए एक रोडमैप' (2020 में अपनाया गया) द्वारा निर्देशित बहुआयामी साझेदारी, निम्नलिखित पहलुओं में अधिक आपसी समृद्धि और वैश्विक स्थिरता की दिशा में विकसित हो रही है<sup>1</sup>:



## भारत और EU की पिछली भागीदारी

भारत-EU पार्टनरशिप दशकों में विकसित हुई है, जिसकी शुरुआत बेसिक डिप्लोमैटिक बातचीत से हुई और यह एक मल्टीफेसटेड स्ट्रेटेजिक गठबंधन में बदल गई, जिसमें राजनीतिक बातचीत, आर्थिक सहयोग, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन और टेक्नोलॉजी जैसी ग्लोबल चुनौतियाँ शामिल हैं। 1960 के दशक में शुरुआती पहचान से लेकर 21वीं सदी में सालाना समिट और जॉइंट पहलों की स्थापना तक,

ये संबंध काफी आगे बढ़े हैं, जो व्यापार, निवेश और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपसी हितों को दिखाते हैं।

### शुरुआती बुनियाद

भारत और EU के बीच राजनयिक संबंध 1960 के दशक की शुरुआत से हैं, जिसमें भारत 1962 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी (EEC) के साथ संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। इसने औपचारिक सहयोग की नींव रखी, जिसका नतीजा 1993 के संयुक्त राजनीतिक बयान और 1994 के सहयोग समझौते के रूप में सामने आया, जिसका मकसद द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना था।

### 2000 के दशक की शुरुआत में हासिल किए गए मुख्य पड़ाव

2000 के दशक की शुरुआत में, कई अहम घटनाओं ने इस पार्टनरशिप को आकार दिया। पहला भारत-ईयू शिखर सम्मेलन जून 2000 में लिस्बन में हुआ, जिसने राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर सालाना उच्च-स्तरीय बातचीत की शुरुआत की। इसके बाद 2004 में द हेग में 5वें शिखर सम्मेलन में इसे रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया, जिससे इसका दायरा व्यापार से बढ़कर सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान तक फैल गया।

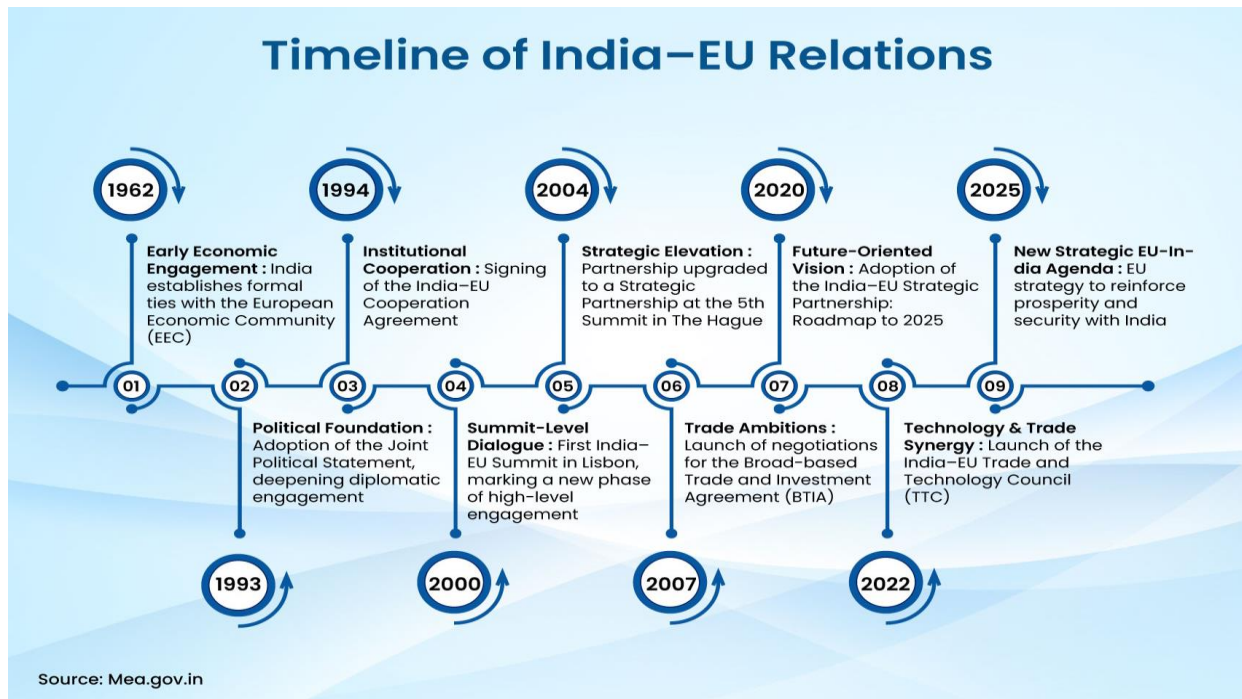
### भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में हालिया सफलता

2000 के दशक की शुरुआत की महत्वपूर्ण घटनाओं के विपरीत, जिन्होंने फ्रेमवर्क स्थापित किया था, जुलाई 2020 में 'भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी: 2025 के लिए एक रोडमैप' को अपनाने, मई 2021 में मुक्त व्यापार और निवेश वार्ताओं को फिर से शुरू करने, और अप्रैल 2022 में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) के लॉन्च के साथ विकास में तेजी आई है। फरवरी 2025 में नई दिल्ली में TTC की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक ने इसे और आगे बढ़ाया, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा दिया, जो मूलभूत संवादों से कार्रवाई योग्य, प्रौद्योगिकी-संचालित साझेदारियों की ओर एक बदलाव का संकेत है।

### भारत-ईयू संवाद - रणनीतिक साझेदारी संरचना

पिछले एक दशक में भारत-ईयू संबंध काफी गहरे हुए हैं, जो मुख्य रूप से बातचीत पर आधारित बातचीत से रक्षा, बुनियादी ढांचे, निवेश, श्रम गतिशीलता और उभरती वैश्विक प्राथमिकताओं में कार्रवाई योग्य, रणनीतिक सहयोग में बदल गए हैं।

'भारत - ईयू रणनीतिक साझेदारी: 2025 के लिए एक रोडमैप' इस विकास को दिशा देने में महत्वपूर्ण रहा है, जिसका नतीजा प्रस्तावित सुरक्षा और रक्षा साझेदारी और व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) जैसी उच्च-स्तरीय प्रतिबद्धताओं के रूप में सामने आया है, जो भारत को जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित करता है।



## व्यापार और आर्थिक फोकस

व्यापार एक मुख्य आधार रहा है, जिसमें EU एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में उभरा है। भारत और EU के बीच द्विपक्षीय माल व्यापार में काफी वृद्धि हुई है, जो 2024-25 में \$136 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें EU से भारत को होने वाले निर्यात में मशीनरी, परिवहन उपकरण और रसायन शामिल हैं, और भारत से होने वाले आयात में मशीनरी, रसायन, बेस मेटल, खनिज उत्पाद और कपड़ा शामिल हैं।

इसके अलावा, 2019 से 2024 तक, भारत-EU के बीच सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि देखी गई, जिसमें भारतीय निर्यात 2019 में EUR 19 बिलियन से बढ़कर 2024 में EUR 37 बिलियन हो गया। इसके अलावा, EU से आयात में भी वृद्धि हुई, जो 2024 में EUR 29 बिलियन तक पहुंच गया।

## रक्षा और सुरक्षा

2025 में भारत-यूरोपीय संघ के सुरक्षा और रक्षा संबंध काफी गहरे हुए हैं, जिसकी पहचान फरवरी में कमिशनरों के कॉलेज की भारत यात्रा के दौरान जारी लीडर्स स्टेटमेंट से हुई, जिसमें सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर विचार करने पर सहमति बनी और इसमें यूरोपीय संघ के रक्षा और अंतरिक्ष आयुक्त और भारत के रक्षा राज्य मंत्री के बीच बातचीत भी शामिल थी।

यह गति दिसंबर 2025 में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के एक प्रतिनिधिमंडल के ब्रुसेल्स दौरे के साथ जारी रही, जिसने यूरोपीय संघ के आयुक्त के साथ बातचीत की और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा दिया। सितंबर 2025 में, यूरोपीय संघ की राजनीतिक और सुरक्षा समिति - जो सभी 27 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती है - ने एशिया का अपना पहला दौरा किया, और रणनीतिक संवाद को आगे बढ़ाने के लिए भारत में विदेश सचिव, उप एनएसए और सचिव (पश्चिम) के साथ उच्च-स्तरीय बैठकें कीं।

इन प्रयासों के पूरक के रूप में, संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया है, जिसमें जून 2025 में हिंद महासागर, अक्टूबर 2023 में गिनी की खाड़ी और जून 2021 में अदन की खाड़ी शामिल हैं, साथ ही 2018 और 2019 में सोमालिया के पास मानवीय सहायता के लिए सहयोगी एस्कॉर्ट ऑपरेशन भी किए गए।

21 जनवरी, 2026 को यूरोपियन पार्लियामेंट की पूरी मीटिंग में एक अहम भाषण में, EU के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के हाई रिप्रेजेंटेटिव ने नई दिल्ली में होने वाले 16वें EU-इंडिया समिट को दोनों पक्षों के बीच गहरी सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम मौका बताया। EU ने भारत के साथ एक नई सुरक्षा और रक्षा पार्टनरशिप पर आगे बढ़ने पर सहमति जताई है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, साइबर डिफेंस और आतंकवाद विरोधी जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा।

## स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु

ऊर्जा और जलवायु सहयोग भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी का एक मुख्य स्तंभ है, जो सतत विकास, जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के प्रति साझा प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। भारत-यूरोपीय संघ ऊर्जा और जलवायु जुड़ाव के केंद्र में स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी (CECP) है, जिसे 2016 में स्थापित किया गया था, और नवंबर 2024 में इसका तीसरा चरण अपनाया गया, जो द्विपक्षीय

सहयोग के बढ़ते दायरे को दर्शाता है। यूरोपीय संघ 2018 से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भागीदार रहा है, जो सौर ऊर्जा के विस्तार का समर्थन करता है, जबकि यूरोपीय निवेश बैंक चुनिंदा भारतीय शहरों में शहरी रेल और मेट्रो सिस्टम सहित स्थायी परिवहन और शहरी गतिशीलता परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

भारत-यूरोपीय संघ सहयोग में अपतटीय पवन ऊर्जा, गैस बुनियादी ढांचे का विकास, मीथेन उत्सर्जन में कमी, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल हैं, और मार्च 2021 में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) में यूरोपीय संघ के शामिल होने से जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे पर साझा प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है। उन्नत वैज्ञानिक क्षेत्रों में, भारत और यूरोपीय संघ ने जुलाई 2020 में EURATOM के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर एक R&D समझौते पर हस्ताक्षर किए, और भारत 2017 से CERN का एक सहयोगी सदस्य रहा है।

### कनेक्टिविटी

भारत और यूरोपीय संघ ने अपनी पार्टनरशिप के एक रणनीतिक स्तंभ के तौर पर कनेक्टिविटी पर अपना सहयोग लगातार बढ़ाया है, जिसका मकसद क्षेत्रों में टिकाऊ, समावेशी और मज़बूत संपर्क को बढ़ावा देना है। भारत-यूरोपीय संघ की कनेक्टिविटी पहल का मकसद आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना और द्विपक्षीय जुड़ाव से परे संतुलित विकास को सपोर्ट करना है।

भारत-यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप (2021) - 2021 में शुरू की गई, भारत-यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप का मकसद ट्रांसपोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी नेटवर्क में सहयोग को मज़बूत करना है, साथ ही लोगों, सामान, सेवाओं, डेटा और पूंजी की आसान आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है।

त्रिपक्षीय विकास सहयोग (जून 2025) : जून 2025 में, भारत और यूरोपीय संघ ने त्रिपक्षीय विकास सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की, जिससे तीसरे देशों में विकास परियोजनाओं को संयुक्त रूप से लागू करना संभव हो सकेगा।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) (सितंबर 2023): सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर, भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की।

### विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी का एक मुख्य स्तंभ है, जिसे संस्थागत ढांचे का समर्थन प्राप्त है जो सहयोगी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। द्विपक्षीय जुड़ाव 2007 में हस्ताक्षरित विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर आधारित है, जिसमें एक संयुक्त



संचालन समिति स्मार्ट ग्रिड, जल, टीके, आईसीटी, ध्रुवीय विज्ञान और यूरोपीय अनुसंधान परिषद के साथ काम करने वाले युवा वैज्ञानिकों की गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में सहयोग का मार्गदर्शन करती है। इसके अलावा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय अनुसंधान और नवाचार फ्रेमवर्क कार्यक्रम "होराइजन 2020" के तहत चयनित परियोजनाओं में भारतीय भागीदारी का समर्थन करने के लिए एक सह-वित्तपोषण तंत्र स्थापित किया है, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और ध्रुवीय अनुसंधान में।

### भारत-ईयू अंतरिक्ष सहयोग

अंतरिक्ष सहयोग भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो दशकों के तकनीकी सहयोग और बढ़ते संस्थागत जुड़ाव पर आधारित है। अंतरिक्ष में भारत-ईयू का जुड़ाव 1980 के दशक से है, जब भारतीय उपग्रहों को यूरोप के एरियन लॉन्चर का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। इसके बाद, यूरोपीय आयोग और अंतरिक्ष विभाग के बीच सहयोग समझौते ने पृथ्वी अवलोकन में सहयोग को मजबूत किया, जिसमें पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों से डेटा तक आपसी पहुंच शामिल है। इसके साथ ही, इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने क्रॉस-सपोर्ट व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे नेविगेशन, संचालन और डेटा हैंडलिंग में आदान-प्रदान संभव हुआ है, जिसमें चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 जैसे प्रमुख मिशनों के दौरान भी शामिल है। परिचालन सहयोग को और दर्शाते हुए, ईएसए के प्रोबा-3 मिशन को दिसंबर 2024 में इसरो के पीएसएलवी-एक्सएल द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।

इन परिचालन संबंधों के साथ उच्च-स्तरीय संस्थागत जुड़ाव भी रहा है। फरवरी 2025 में, रक्षा और अंतरिक्ष के लिए यूरोपीय संघ के आयुक्त ने नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री से मुलाकात कर बेहतर सहयोग के तरीकों पर चर्चा की। इसके बाद नवंबर 2025 में ब्रुसेल्स में पहला भारत-ईयू अंतरिक्ष संवाद हुआ, जिसने संरचित जुड़ाव के लिए एक समर्पित मंच प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, मई 2025 में, इसरो और ईएसए ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सहयोग पर एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो भविष्योन्मुखी अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार का प्रतीक है।

### प्रवासन और गतिशीलता

शुरुआती प्रवासन संवाद 2016 के प्रवासन और गतिशीलता पर सामान्य एजेंडा (CAMP) जैसे संरचित ढांचों में विकसित हुए हैं, जो कुशल श्रमिकों के प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा और EU की जनसांख्यिकीय ज़रूरतों और भारत के कार्यबल अधिशेष को पूरा करने के लिए व्यवस्थित प्रवासन पर ज़ोर देते हैं।

प्रवासन और गतिशीलता पर 9वीं उच्च-स्तरीय वार्ता (नवंबर 2025) ने कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया, जिसमें ICT पेशेवरों के लिए भारत में एक पायलट यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का प्रस्ताव दिया गया और युवा पेशेवरों के लिए व्यापक गतिशीलता ढांचे की खोज की गई। 2024 के अंत में, कुल

931,607 भारतीय नागरिक EU में रहते थे, जो ब्लू कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ा समूह (20.8%) था (2024 में 16,268)।

भारतीय छात्र इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में से रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में, यूरोप भर के प्रमुख संस्थानों में अध्ययन और काम करने के लिए भारतीय छात्रों को 6,000 से अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई हैं।

रणनीतिक रूप से, यह प्रवासन साझेदारी के माध्यम से भारत की राजनयिक पहुंच का समर्थन करता है, जो नए यूरोपीय मिशन जैसे विस्तार के बीच मानव-केंद्रित संबंधों और वैश्विक प्रतिभा प्रवाह को बढ़ाता है। भारत की प्रगति सुव्यवस्थित कानूनी मार्गों और योग्यता मान्यता में स्पष्ट है, जो इसे भारत और EU दोनों देशों के लिए एक प्रमुख प्रतिभा स्रोत के रूप में स्थापित करता है।

## निष्कर्ष

भारत-यूरोपीय संघ संबंध साझा मूल्यों, बढ़ते आर्थिक संबंधों और सामान्य रणनीतिक हितों पर आधारित एक मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। बढ़ता व्यापार, स्थिर यूरोपीय संघ निवेश और कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और श्रम गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में सहयोग एक ऐसी साझेदारी को दर्शाता है जो स्पष्ट और व्यावहारिक परिणाम दे रही है।

ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ग्लोबल गेटवे, IMEC जैसी पहल और FTA वार्ताओं में प्रगति भारत और यूरोपीय संघ के बीच गहरे संस्थागत तालमेल को दर्शाती है। इसी गति को आगे बढ़ाते हुए, भारत द्वारा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, महामहिम श्री एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा, और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, महामहिम सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन को 25-27 जनवरी 2026 को राजकीय यात्रा के लिए दिया गया निमंत्रण, भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को अपनी वैश्विक और यूरोपीय रणनीति के मुख्य स्तंभ के रूप में ऊपर उठाने के सरकारी इरादे को रेखांकित करता है।

**संदर्भ:**

**विदेश मंत्रालय:**

- [https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/32828/IndiaEU\\_Strategic\\_Partnership\\_A\\_Roadmap\\_to\\_2025](https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/32828/IndiaEU_Strategic_Partnership_A_Roadmap_to_2025)
- <https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India-EU-feb-2025.pdf>
- <https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India-EU-feb-2025.pdf>
- <https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India-EU-feb-2025.pdf>
- <https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/39113/Joint+Statement+Second+Meeting+of+the+IndiaEU+Trade+and+Technology+Council+New+Delhi+February+28+2025>
- <https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/39112/>
- <https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/40336>
- <https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/40134/>



- [https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/33854/IndiaEU\\_Connectivity\\_Partnership](https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/33854/IndiaEU_Connectivity_Partnership)
- <https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/37091>
- [https://www.mea.gov.in/images/attach/migration\\_and\\_mobility\\_between\\_india\\_and\\_the\\_european\\_union.pdf](https://www.mea.gov.in/images/attach/migration_and_mobility_between_india_and_the_european_union.pdf)
- <https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/40296/9th+IndiaEU+High+Level+Dialogue+for+Migration+and+Mobility+New+Delhi+November+12+2025>
- <https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/40591>

## यूरोस्टेट

- [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Residence\\_permits\\_-\\_statistics\\_on\\_stock\\_of\\_permits\\_at\\_the\\_end\\_of\\_the\\_year#Non-EU\\_citizens\\_with\\_a\\_residence\\_permit](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Residence_permits_-_statistics_on_stock_of_permits_at_the_end_of_the_year#Non-EU_citizens_with_a_residence_permit)
- [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Residence\\_permits\\_%E2%80%93\\_statistics\\_on\\_authorisations\\_to\\_reside\\_and\\_work](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Residence_permits_%E2%80%93_statistics_on_authorisations_to_reside_and_work)

## यूरोपीय संघ आयोग

- [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_25\\_2116](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2116)

## पीआईबी शोध

## पीके/केसी/एनएम